देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 26.07.2025
समय 0720

मुख्य समाचार :—

- प्रदेश सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए किया।
- आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बांध परियोजनाओं को पानी छोड़ने से पहले सूचना देने और रियल टाइम डेटा साझा करने के निर्देश दिए।
- प्रदेश में एप्पल और कीवी मिशन के तहत अब डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से किसानों को अनुदान राशि दी जाएगी।
- राज्य के विभिन्न हिस्सों में कल रात से रुक—रुक कर बारिश का सिलसिला जारी।

<u>अनुदान राशि</u>

प्रदेश सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अलावा उन्हें वार्षिक अनुदान राशि के रूप में तीन लाख रूपये मिलते रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। सैनिक कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दे दिया है। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार, सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों की रक्षा के लिए निरंतर ठोस और प्रभावी निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड न केवल देवभूमि है, बल्कि वीरभूमि भी है, जिसने देश को अनेक वीर सैनिक दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सीमाएं हमारे वीर सैनिकों के शौर्य, साहस और बलिदान के कारण सुरक्षित हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सैनिकों की वीरता, समर्पण और बलिदान का सम्मान करे।

<u>आपदा बैठक</u>

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव, विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश में संचालित सभी बांध परियोजनाओं के अधिकारियों को पानी छोड़ने से पहले इसकी सूचना राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के साथ ही संबंधित जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट करने को कहा कि छोड़ा गया पानी कितने समय में किन क्षेत्रों तक पहुंचेगा और वहां क्या प्रभाव हो सकता है, ताकि आमजन को समय से सतर्क किया जा सके। श्री सुमन सचिवालय में प्रदेश की सभी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड जल विद्युत निगम और केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने पूर्व चेतावनी तंत्र के अंतर्गत लगे सेंसरों द्वारा प्राप्त नदी जलस्तर और डिस्चार्ज डेटा को एपीआई के माध्यम से रियल टाइम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ साझा करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के माध्यम से जलस्तर की निगरानी की जा सके। बैठक में सभी एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी परियोजनाओं के लिए आपातकालीन

कार्य योजना और मानक संचालन प्रक्रिया शीघ्र तैयार कर प्राधिकरण के साथ साझा करें तथा उसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करें।

कारगिल दिवस

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर देश की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अद्वितीय साहस, अदम्य शौर्य और उच्चतम रणनीतिक कौशल का प्रतीक है। यह एक ऐतिहासिक विजय थी, जिसमें देश के बहादुर सैनिकों ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में भी अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा की और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। राज्यपाल ने कहा कि वीरभूमि उत्तराखण्ड के अनेक जांबाज सपूतों ने भी इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर राज्य और देश का गौरव बढ़ाया। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड की वीरता, देशभक्ति और बलिदान की परंपरा अटूट रही है, जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य को नमन करते हुए कहा कि देश के लिये अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में बड़ी संख्या में उत्तराखण्ड के वीर सपूतों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी सैनिक परम्परा और देशभक्ति की विरासत पर गर्व हैं।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि से पोषित योजनाओं को लेकर उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों को उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराएं। उन्होंने नाबार्ड के अधिकारियों और विभागों को आने वाले वर्षों में नाबार्ड का बजट 1200 करोड़ रूपए तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अगस्त माह के अंत तक सभी विभागों को अपने प्रस्ताव उपलब्ध कराने और धीमी गति से चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने को कहा। उन्होंने नाबार्ड को उनके पोर्टल की खामियों को भी शीघ्र दूर किए जाने के निर्देश दिए, ताकि विभाग पोर्टल पर अपडेट कर सकें।

डिजिटल भुगतान

प्रदेश में एप्पल और कीवी मिशन के तहत किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि अब डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए 'अपुणि सरकार' पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी उद्यान विभाग कार्मिकों की लॉग इन आईडी तैयार कर उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में इस संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां योजना के तहत अनुदान वितरण सीबीडीसी के माध्यम से किया जाएगा। यह पोर्टल भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और संबंधित बैंकों के सहयोग से उत्तराखंड औद्यानिक परिषद की ओर से विकसित किया जा रहा है और यह अंतिम चरण में है। विभागीय मंत्री ने उत्तराखंड औद्यानिक परिषद की ओर से की जा रही तैयारियों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि अगस्त माह के अंत तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नई प्रणाली के लागू होने से योजना की सभी प्रक्रियाएं जैसेपूरी तरह पेपरलेस हो जायेंगी। श्री जोशी ने कहा कि यह अभिनव प्रयास पारदर्शिता, त्वरित क्रियान्वयन और बजट के समुचित उपयोग की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

मौसम

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से रुक–रुक कर मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, यह सिलसिला आने वाले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है।

इसी बीच, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में कल कहीं–कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है।

मुलाकात

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में उत्तराखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति अमित सिन्हा ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने श्री सिन्हा को नव सृजित विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए सक्रिय और नवाचारपूर्ण प्रयासों की अपेक्षा की। उन्होंने खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देने, खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा राज्य के युवाओं में खेलों के प्रति रुचि विकसित करने पर बल दिया।

और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

राज्य सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली अनुदान राशि को तीन गुना बढ़ा दिया है। यह ख़बर आज सभी समाचार पत्र की सुर्खियों में है। अमर उजाला लिखता है– परमवीर चक्र विजेताओं को मिलेंगे डेढ करोड़ रुपए; सीएम ने कारगिल दिवस विजय की पूर्व संध्या पर दिया तोहफा।

ईको टूरिज्म घोटाले की सीबाआई जांच की संस्तुति, दैनिक जागरण का शीर्षक है। समाचार पत्र के अनुसार मुनस्यारी आरक्षित वन क्षेत्र में नियम ताक पर रख कर निर्माण किया गया और ईको हट निर्माण में अनियमितता पाए जाने के साथ ही धन के दुरुपयोग की बात सामने आई। इस संबंध में सात सौ पन्नों की रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश को हिंदुस्तान समाचार पत्र अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखता है– सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट होगा। समाचार पत्र ने लिखा है– सीएम ने जर्जर स्कूलों में बच्चों को किसी भी सूरत में न बिठाने के निर्देश दिए, राज्य के एक हजार एक सौ बहत्तर स्कूल अति संवेदनशील श्रेणी में।

राज्य में सहकारिता के क्षेत्र को मज़बूत और आधुनिक बनाने के लिये व्यावसायिक नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र के अनुसार इसके लिये सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को बिजनेस प्लान तैयार करने के निर्देश दिये हैं।

राज्य सरकार ने नाबार्ड का बजट बारह सौ करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। नवोदय टाइम्स इस शीर्षक के साथ लिखता है– मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बजट को बढाने के लिये सभी विभागों को सोर्स ऑफ फंड तलाशने की आवश्यकता बताई।